an>

Title: Need to revamp the postal services in the country particularly in Surat Parliamentary Constituency, Gujarat .

*mo1

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): पूरे देशभर में डाक विभाग के तकरीबन 1,55,000 डाकघर कार्यरत हैं। उन डाकघरों में तकरीबन 25,000 डाकघर गुजरात में मौजूद हैं। उनमें मॉडर्न टेक्नॉलोजी की सेवा उपलब्ध है एवं विभाग में नई-नई सेवाएं जैसे सोने की बिक्री करना, रेलवे का आरक्षण, अमरनाथ यात्रा की बुकिंग, विदेशी मनी ऑर्डर इत्यादि सेवाएंÃ¬ उपलब्ध की जाती है। सरकार के द्वारा डाकघरों में नई-नई सेवाएं तो दी जाती हैं लेकिन ज्यादातर डाकघर ऐसे हैं जो किराये के मकान में चल रहे हैं। उनमें से कई डाकघर मेरी जानकारी के मुताबिक 50 से 60 साल पुराने जर्जर मकानों में चल रहे हैं। ऐसे डाकघर सूरत (गुजरात) में सगरामपुरा पुतली, रांदेर, नक्खुम, पांडेसरा, जर्जर मकान में चल रहे हैं। सगरामपुरा पुतली डाकघर के लिए 3-3 बार टेण्डर आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसे कितने जर्जर डाकघर देशभर में और सूरत, गुजरात में मौजूद हैं? इन डाक भवनों के निर्माण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं? इन भवनों के लिए सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा फण्ड आवंटन करना चाहिए और ऐसे जर्जर डाक भवनों को बदलने की आवश्यकता है।

आज देश में गांव और शहरों की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। डाक विभाग में 6 लाख कर्मचारी आज से 10 साल पहले कार्यरत थे। उसमे से करीब 50 हज़ार से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। उनकी वजह से आम आदमी को डाक समय पर नहीं मिलती। जैसे सरकारी नौकरी इच्छुक लोगों को तो साक्षात्कार हो जाने के बाद डाक मिलती है जिसकी वजह से देशभर में 80 हब सेंटर बनाये हैं और जर्मनी और इंग्लैण्ड की डाक व्यवस्था का अमल किया जा रहा है जैसे गुजरात में 5 जगह हब सेंटर बनाये गये हैं। सूरत में 5 लाख डाक आर.एम.एस. में इकट्ठी हो गई है। पहले ट्रेनों में डायरेक्ट सोर्टिंग व्यवस्था होती थी। वह बंद हो जाने की वजह से आम आदमी डाक वितरण से परेशान हो चुका है। मैं जानना चाहती हूं कि गुजरात और सूरत में रिक्त पद भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं? क्या सरकार इस बात का जानती है कि रिक्त पदें की वजह से हमारी डाक सेवाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं?

भारत सरकार के डाक विभाग में कार्यरत अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक अधिकारियों का कार्यकाल 4 साल का होता है। उसके बाद उसे सरकारी नियमों के तहत स्थानांतरित किया जाता है लेकिन गुजरात सर्कल के वड़ोदरा रीजन में पोस्ट मास्टर जनरल और निर्देशक द्वारा अप्रेल 2012 में 21 वरिÂठ अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें से कई अधिकारियों का कार्यकाल तो सिर्फ 4 से 8 महीना ही था। इनमें से कई अधिकारियों ने अपने परिवार के लिए एवं बच्चों की पढ़ाई की वजह से अपनी पंसदीदा जगह पाने के लिए मांग की थी। यदि इन अधिकारियों को उनकी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग कर दी गई होती तो सरकारी खर्च करीब 20 लाख रूपए बच सकते थे।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि यह आदेश तुरंत ही रद्द किया जाए एवं जो सरकारी खर्च हुए हैं, उसे संबंधित अधिकारियों की तनख्वाह से रिकवर किया जाए।